Addressing Press at Ghatampur, Uttar Pradesh

October 20, 2016

मुफ्त में बिजली कनेक्शन दी जाये इसके लिए केंद्र सरकार ने शत-प्रतिशत घरों के लिए पैसे का आवंटन कर लिया है | Intensive electrification जिसमें मझले, टोले, धानी, इन सब तक पहुंचे बिजली उसके लिए लगभग 70,000 गावों के लिए पैसा आवंटन कर दिया है | लेकिन पैसा तभी मिल सकता है पहली किश्त तो सभी जगह पहुँच गई है लेकिन जब जो मापदंड दिए गए हैं और यह मापदंड की पूरी जानकारियां इस किताब में है आपको जो-जो चाहिए आप सांसद जी से ले सकते हैं | हर एक मापदंड क्या-क्या करना पड़ता है जिससे पैसे का actual utilization certificate हो, quality का certificate हो कि quality में कोई कमी नहीं है, जो-जो sign board लगने हैं कि यह केंद्र सरकार ने यह विद्युतीकरण के लिए योजना लायी है उसके अंतर्गत काम हुआ है | अगर यह सब मापदंड पूरे हो जाएं और देश भर में इसका पैसा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी जैसे-जैसे अधिकारी इसकी certificate देते हैं वैसे-वैसे पैसा पहुँच जाता है |

प्रश्न: मंत्री जी 2012 में शिलान्यास रखा गया था ?

उत्तर: मैंने कोई शिलान्यास नहीं रखा, मैंने स्पष्ट कर दिया, मैं आज धरातल पे काम शुरू करने आया हूँ| 2012 में जो शिलान्यास रखा गया वो मात्र जनता को भ्रमित किया गया है | मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस समय का कार्यक्रम, 2012 का कार्यक्रम मात्र जनता को भ्रमित किया गया, ना कोयले का block का final allocation किया गया, ना cabinet द्वारा यहाँ की investment का approval हुआ, ना तभी ज़मीन इस प्रोजेक्ट के हाथ में थी | मैंने जैसा अभी बताया तभी सिर्फ मात्र 73 करोड़ रुपये, 73.65 करोड़ रुपये sanction हुए थे इस प्रोजेक्ट के लिए | अगर आप में से किसी को लगता है कि बिना ज़मीन के, बिना environment clearance के, बिना कोयले के final block allotment के, बिना कंपनियों को order दिए, बिना tender खोले, अगर यहाँ plant लग सकता था तो आप शायद ज्यादा अच्छा समझते हैं ! लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करती जब तक शत-प्रतिशत काम शुरू होने की तैयारी ना हो |

प्रश्न: लोकार्पण कब होगा मंत्री जी ?

उत्तर: यहाँ पे विद्युतीकरण हो जाएगा ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा; दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोकार्पण तो नहीं हुआ मैं यहाँ धरातल पे काम शुरू करने आया हूँ | पर अब ये काम शुरू हो के इनके अनुमान के हिसाब से दिसम्बर 2020 तक यह काम पूरा होगा लेकिन मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस काम को 2019 तक ख़त्म करने के लिए एक साल हर एक काम को और तेज़ गति देके पहले ख़त्म किया जाए |

प्रश्न: मंत्री जी यह बताएं नए पॉवर प्लांट्स लग रहे हैं ..... ?

उत्तर: उत्तर प्रदेश में उदय, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, के तहत ... एक पॉवर एक्सचेंज है जिसको विद्युत् प्रवाह कहते हैं, आप भी अपने मोबाइल फ़ोन पर विद्युत् प्रवाह को डाउनलोड कर लीजिए| देश में जा के विद्युत का काम करता हूँ अगर उत्तर प्रदेश आ के विद्युत् की बात नहीं करूँगा तो और क्या काम करूँगा|

प्रश्न: वडोदरा में मेरी आपसे बात हुई थी अभी हाल ही में, तब आपने यह बात स्वीकारी थी कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश में कि बिजली को एक सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या यह, नहीं वडोदरा में बैठकर यू.पी. पर कमेंट करना आसान है, यू.पी. में बैठकर आप यह मानते हैं कि?

उत्तर: नहीं| यू.पी. में भी बैठके में बोलता हूँ | सियासी मुद्दा कौन बनाता है उसके हाथ में है, मुझे तो ऊर्जा का काम करना है मैं तो ऊर्जा मंत्री हूँ | मैं पैसा आवंटन कर सकता हूँ, काम तो धरातल पे आप के प्रदेश में ही होना पड़ेगा |

प्रश्न: आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो आपने 25,000 हज़ार करोड़ last दिए हैं, काम सही हो रहा है ? संतोषजनक है ?

उत्तर: मैंने अभी-अभी जानकारी दी अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो जितनी जानकारी चाहिए यहाँ पे है| आप उसमें से आकलन खुद निकालिए | बारहवी पंचवर्षीय योजना अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, 2012-17 उसमें लगभग 32 लाख गरीबों के घर बिजली पहुंचनी थी, मात्र सवा लाख घरों तक पहुंची है|

प्रश्न: 828 hectare ज़मीन यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने acquire किया, उसी प्रकार जयस्वाल कोयला मंत्री थे उन्होंने coal block का आवंटन किया | क्या आप उनके योगदान को इसमें नहीं मानते हैं?

उत्तर: नहीं, आप कुछ उनके दूत बनके आए हैं क्या? मुझे आप यह बताएं जब ज़मीन 2014 नवम्बर में मिली तो आप कैसे बोल सकते हो उन्होंने आवंटन करी| जब कोयले का block मैंने sign करके sanction किया तो 2012 तक कहाँ था कोयले का block, in-principle approval आपको चाहिए मैं 500 block के दे सकता हूँ उससे कोयले का block नहीं मिलता है |

उत्तर प्रदेश में उदय, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत लगभग 30,000 करोड़ से भी अधिक लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिले, यहाँ की डिस्कॉम को मिले जो लाभ जनता तक पहुँच पाए | और आगे हर वर्ष 10,000 करोड़ से भी अधिक लाभ डिस्कॉम को 2019 के आगे हर वर्ष उदय की योजना का पालन करने से मिलेगा | मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करूँगा कि जैसे ही उदय योजना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी 2015 नवम्बर में उसके चन्द ही महीने बाद उत्तर प्रदेश ने उदय योजना के साथ अपने आपको जोड़ा, उसका agreement sign किया और उसमें अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं वह सभी लक्ष्य हमने जनता और मीडिया के समक्ष website पे डाल रखे हैं | अब हमने ऊर्जा का एक app निकाला है ऊर्जा के app में हम उस लक्ष्य के सामने क्या-क्या किया जा रहा है और क्या-क्या AT&C loss, power cut यह सब सुधार किया जा रहा है वह हम जनता के समक्ष रखते हैं | किसी कारण से, मुझे कारण नहीं मालूम, पर 2016 अगस्त से वह जानकारियाँ आनी बंद हो गई है तो मैं अधिकारियों से दरख्वास्त करूँगा कि वे जानकारियाँ ना रोके | जनता का अधिकार है कि वह जानकारी जनता तक पहुंचे, हाँ तो मेहरबानी करके अगस्त के बाद जानकारी आई नहीं है तो सभी जानकारियाँ दी जायें जिससे ऊर्जा app में latest, real-time information जनता को मिले | और देखिए मेरे भी काम में कोई कमी होती है तो मैं सीधा website पे डालता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि महाराष्ट्र के में कोई कमी हो तो वह छुपाऊँ, गुजरात की कमी छुपाऊँ और उत्तर प्रदेश की रखूं, पूरे देश की, हर राज्य की, कोई भी राज्य सरकार हो, जैसा माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, कोयले के आवंटन में कभी भेदभाव नहीं किया | उत्तर प्रदेश को मैंने कोयले के ब्लाक का एक और आवंटन किया है, यहाँ का तो मैंने बताया साउथ पच्वाडा, 54 करोड़ टन का ब्लाक | मैंने एक और ब्लाक दिया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश को, शहरपुर जमरपानी उसमें 73 करोड़ टन

के कोयले की capacity है | जबकि उत्तर प्रदेश को पहले कांग्रेस की सरकार ने एक छोटा ब्लाक दिया था उस ब्लाक में शायद 20-22 करोड़ टन कोयला था, मैंने उस 20-22 करोड़ टन के कोयले का block जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध किया गया, अवैध घोषित किया गया, रद्द किया गया क्यूंकि उसमें भ्रष्टाचार हुआ था | उस समय के सभी कोयले के blocks को रद्द किया गया उसके बदले 22 करोड़ के सामने 73 करोड़ टन के block का मैंने आवंटन उत्तर प्रदेश को किया | किसी प्रकार का भेदभाव कोई सरकार कोई राज्य के साथ इस सरकार ने नहीं किया बल्कि पूर्वी राज्यों को अधिक सुविधाएं मिले, अधिक पैसे का आवंटन हो, अधिक लाभ पहुंचे जिससे पूर्वी भारत भी विकास से और प्रगति से वंचित नहीं रहे, ये हमारा काम है |

एक power exchange है जिसको विद्युत् प्रवाह कहते हैं, आप भी अपने मोबाइल फ़ोन पे विद्युत् प्रवाह को download कर लीजिए | विद्युत् प्रवाह में power exchange में पूरे समय जानकारी मिलती है - किस दाम पे कितनी बिजली उपलब्ध है और उसमें से बिजली जब भी कोई राज्य को कमी पड़ती है वह खरीद सकता है | अभी के समय, अभी, ये क्षण, 2.06 मिनट हुए हैं आपकी घडी में, तो जो 2 बजे से 2.15 बजे का स्लॉट है 15 मिनट का उसमें power exchange में अभी के समय 2.40 रूपये में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, सब में उपलब्ध है | और कितनी बिजली है 3,400 MW| तो लोग खरीद सकते हैं और जनता की सेवा कर सकते हैं |

प्रश्न: सर मंत्री जी ने अभी कहा दिवाली से यू.पी. के शहरों को ज्यादा बिजली देने जा रहा हूँ, क्या यह माना जाए कि केंद्र सरकार से लेके यू.पी. के लोगों को बिजली दी जा रही है ?

उत्तर: यह power exchange से मिलेगी और कुछ भी कमी पड़े मैं आज ऐलान करता हूँ उत्तर प्रदेश को जितनी बिजली चाहिए केंद्र सरकार से दी जाएगी |

....प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने, जिन्होंने स्वयं गरीबी, अँधेरा अपने जीवन में व्यतीत किया है, महसूस किया है उन्होंने जब कमान संभाली भारत की तब सबसे पहली और प्रमुख निर्णय और घोषणा यह की कि 2022 तक पूरे देश में हर घर तक चौबीसों घंटे बिजली पहुंचेगी, किसानों को पर्याप्त बिजली मिलेगी, उद्योगीकरण के लिए पूरी तरीके से बिजली मिलेगी और भारत diesel generator और inverter और kerosene lamp से मुक्ति पाएगा | 2014 में की हुई यह घोषणा के ऊपर पूरी केंद्र सरकार तेज़ गति से लगी हुई है और मुझे आपको आज बताते हुए ख़ुशी होती है कि लगभग पूरे देश

में जहाँ-जहाँ राज्य सरकारें हमें मदद कर रही हैं यह लक्ष्य 2019 तक पूरा कर दिया जाएगा | 2019, यानी पुराने लक्ष्य से 3 साल पहले पूरे देश में हर जगह जहाँ राज्य सरकार का हमें पूर्ण सहयोग मिले हम बिजली पहुंचा देंगे हर घर तक | और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो लगभग आज 7 दशकों तक विद्युत् से वंचित रही है | 2015 में जब आंकड़ा निकाला तब पता चला लगभग 1,80,00,000 घर ऐसे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में, 1,80,00,000 घर जहाँ बिजली पहुंची नहीं है इन सभी घरों तक बिजली पहुंचे और ये लक्ष्य 2022 नहीं 2019 तक किया जाए इसके लिए मैं सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूँ | अभी-अभी विद्युत् मंत्रियों की बैठक हुई और मुझे आपको बताते हुए ख़ुशी होती है कि देश के हर एक राज्य ने यह कहा है कि वह हमारा पूरा सहयोग करके इस लक्ष्य को पूरा करेंगे | मुझे आज आपके MD साहब ने भी आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश भी हमारा सहयोग करेगा क्यूंकि ये जो अभी तक के आंकड़े जब मैं देखता हूँ तब मुझे बड़ा दुःख होता है | अब ये आप चार्ट देखिए, नए गावों तक बिजली पहुँचाने का काम, आखिर पैसा तो पहले ही निर्धारित हो गया था, आवंटन हो गया था | 2009-10 में मात्र 56 गावों में, मात्र 56 गावों 2009-10 में, 2010-11 में 23 नए गावों में, 2011-12 में शून्य, 2012-13 में मात्र 3, 2013-14 में शून्य| 2014-15 में मैं विद्युत् मंत्री बना, कुछ समय लगा समझने के लिए क्या काम हो रहा है फिर तेज़ गति से एक-एक राज्य सरकार से पीछे पड़ा कि काम शुरू हो| और एक ही वर्ष 2014-15 जो मेरा पहला पूरा वर्ष था उसमें लगभग 1305 गावों तक विद्युतीकरण हुआ| इसके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सभी लोग मिलके काम करे और पूरा सहयोग मिले तो यह संभव है कि 2019 तक हर घर तक बिजली पहुंचे और इस देश के कोई विद्यार्थी को अँधेरे में ना पढना पड़े जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार कहा था और एक तरीके से कविता के रूप में कहा था कि - माना अँधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है - तो यह लक्ष्य लेके हम चले हैं और मुझे आप सब से बताते हुए ख़ुशी होती है कि अब 2022 नहीं 2019 तक ही पूरे देश में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का काम पूरा हो जाएगा |

विद्युतीकरण का काम मैं केंद्र से आके एक-एक घर तक तो बिजली नहीं पहुंचा सकता हूँ, कनेक्शन नहीं दे सकता हूँ, एक-एक गाँव में कनेक्शन तो मुझे राज्य सरकार के ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा | तो मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि विकास उस तक पहुंचे और आज जनता भी यह चाहती है कि विकास की प्रवाह से वंचित नहीं रहना चाहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश में हर राज्य और हर घर तक यह काम पूरी तरीके से हो |